



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 24, 1991 (भाद्रपद 2, 1913)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 24, 1991 (BHADRA 2, 1913)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई, दिनांक 19 जुलाई 1991

सं० 3 डब्ल्यू सी ए(4)/3/91-92 — चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा 1(अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु होने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिये हैं।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1	1758	श्री पी० डी० खाडीलकर एफ० सी० ए० द्वारा मेसर्स जो० डी० अपटे एण्ड कं०, 6/1, बुधवार 'पेथ' लक्ष्मी रोड पूने-411 002।	10-4-1991

1	2	3	4
2	1844	श्री पी० सी० त्रिवेदी, एफ० सी० ए० द्वारा इन्जमें आर्ट, नेशनल इन्सुरन्स बिल्डींग, पहली मंजिल, 27, बसेन रोड, फोर्ट, बम्बई-400 001।	08-8-1990
3	6075	श्री बी० डी० बाटीवाला, एफ० सी० ए० ओरियंट हाऊस 666 पारसी कालोनी, दादर, बम्बई-400 014।	19-3-1991
4	6159	श्री जी० एम० जोग, ए० सी० ए० 10, राजमहल, अंधेरी कुर्ली रोड, अंधेरी (पू०) बम्बई-400 069।	01-6-1991

भारतीय विधिज्ञ परिषद

1	2	3	4
5	12161	श्री आर०सी० खतर, ए०सी०ए० व्ही एक्स एल इंडिया लि०, दिग्जाम बुलन मिल्स लि०, एरोझोम रोड, जामनगर-361 006।	12-3-1991
6	39652	श्री एफ०ए० अरन्हा, ए०सी०ए० शाँ. नं० 2, मस्टीन विला, किरोल, विद्याविहार, घाटकोपर, बम्बई-400 086।	03-5-1991

एम०सी० नरसिम्हन
सचिव

कलकत्ता-700071, दिनांक 26 जुलाई 1991

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई० सी०ए० (4)/4/91-92 :—चार्टर्ड प्राप्त लेखा-कार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु होने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिये हैं :—

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	530	श्री सुधीर कुमार घोष, 4/1जी, सेवक वैद्या स्ट्रीट, कलकत्ता-700 029।	25-1-91
2	1987	श्री ईशान चन्द मित्रा, 68बी, बल्लीगंज सर्कुलर रोड, 5 फ्लोर, कलकत्ता-700 031।	6-6-91
3	4173	श्री रमेश चन्द्रा गुप्ता, मैसर्स रमेश सी० गुप्ता एण्ड क०, 33ए, चौखिबी नोड, चट्टर्जी इंटरनेशनल सेंटर, आर० नं० 7ए, 12 फ्लोर, कलकत्ता-700 071।	23-1-91

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1991

विषय I. भाग VI के अध्याय II के नियम 8 का संशोधन
परिषद की फरवरी, 1991 में हुई गत बैठक में परिषद ने ऊपर निविष्ट नियम का संशोधन किया है जो निम्नलिखित संकल्प के रूप में उपवर्णित है :—

संकल्प सं० 12/1991

संकल्प किया जाता है कि भाग VI के अध्याय II में नियम 8 का परन्तुक निम्नलिखित रूप में संशोधित हो :—

परन्तुक में आने वाले “के कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी मामले में” शब्दों को निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर “की ओर से” शब्द रखे जाएं। संशोधित परन्तुक इस प्रकार पढ़ा जाए —

“परन्तु यह नियम किसी ऐसे सदस्य को लागू नहीं होगा जो किसी विधिज्ञ परिषद्, निगमित विधि सोसाइटी या किसी बार एसोसिएशन की ओर से ‘न्याय मित्र’ के रूप में या किसी फीस के बिना उपसंज्ञात होता है।”

II. भाग VI के अध्याय II के नियम 6 का संशोधन
परिषद् की पिछली बैठक में परिषद ने भाग VI के अध्याय II के नियम 6 का भी संशोधन किया जो निम्नलिखित संकल्प के रूप में उपवर्णित है :—

संकल्प सं० 11/1991

संकल्प किया जाता है कि भाग VI अध्याय II के नियमों के नियम 6 के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए :—

“इस नियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय में कोई ऐसा न्यायालय, न्यायपीठ या अधिकरण अभिप्रेत है जिसमें अधिवक्ता का ऊपर वर्णित संबंधी न्यायाधीन, सदस्य या पीठासीन अधिकारी है।”

श्याम मोहन श्रीवास्तव
सचिव

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 अगस्त 1991

सं० 2/1959/डी. एल. आइ. /एफजाम/89/भाग-1/1350—जहां मैसर्स कमला सोलवेंट्स (प्रा.) लि. कर्कर रोड, डिन्डीगुल-4, (टी.एन./20053) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिससे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग

अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूँ। (दिनांक 1-5-89 से 30-4-92 तक)।

अनुसूचा-1।

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लंबा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुत संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवये राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संवये होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वृत्ति में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एकजाम/89/भाग-1/1356—जहाँ मैसर्स भारत ह्यूवी प्लेट्स गण्ड बैसला लि., बी.एच.पी.वी. डाकघर, विशाखापटनम-12, (ए.पी./3495) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या : एस-35014/262/82/पी.एफ.-2(एस एस 2) दिनांक 7-4-86 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूँ, जो दिनांक 18-12-88 से 17-12-91 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 17-12-91 भी शामिल है।

अनुसूचा-11

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा परीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्विष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अन्कूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदाय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिशों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चन करेगा।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

THE INSTITUTE OF CHARTERED**ACCOUNTANTS OF INDIA**

Bombay-400 005, Dated, the 19th July, 1991

No. 3WCA(4)/3/91-92—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of the sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of death, with effect from the date mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1	2	3	4
1.	1758	Shri P.D. Khadilkar, FCA., C/o. M/s. G.D. Apte & Co., 6/1, Budhwar Peth, Laxmi Road, Pune-411 002.	10-4-1991

1	2	3	4
2.	1844	Shri P.C. Trivedi, FCA., C/o. Enjme Art, National Insurance Bldg., 1st Floor, 27, Bastion Road, Fort, Bombay-400 001.	8-8-1990
3.	6075	Shri B.D. Batiwala, FCA., Orient House, 666, Parsi Colony, Dadar, Bombay-400 014.	19-3-1991
4.	6159	Shri G.M. Jog, ACA., 10, Rajmahal, Andheri Kurla Road Andheri (E) Bombay-400 069.	1-6-1991
5.	12161	Shri R.C. Khater, ACA., VXL India Ltd., Digjam Woollen Mills, Aerodrome Road, Jamnagar-361 006.	12-3-1991
6.	39652	Shri F.A. Aranha, ACA. Shop No. 2 Martin Villa, Kirol, Vidyavihar, Ghatkopar, Bombay-400 086.	3-5-1991

M. C. NARASIMHAN,
Secy.

Calcutta-700071, the 26th July, 1991

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/4/91-92—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(i) (a) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names:

Sl. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	530	Shri Sudhir Kr. Ghosh 4/1G Sovak Baidya Street, Calcutta-700 029.	25-1-91
2.	1987	Shri Ishan Ch. Mitra, 68B, Ballygunge Circular Road, 5th floor Calcutta-7000 31.	6-6-91
3.	4173	Shri Ramesh Chandra Gupta, M/s. Ramesh C. Gupta & Co., 33 Chowringhee Road, Chatterjee International Centre, R. No.-7A, 12th floor, Calcutta-700 071.	23-1-91

M.C. NARASIMHAN,
Secy

THE BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi the 6th August 1991

Subject : I. Amendment to Rule 8, Chapter II, Part VI.

At its last meeting in February, 1991 the Council has amended the Rule referred to above as set out in the following Resolution :—

RESOLUTION NO. 12/1991

"RESOLVED that the proviso to Rule 8 in Chapter II, Part VI, be amended as follows :—

The words "in a matter affecting the affairs" occurring in the proviso be deleted and the words "on behalf" be substituted. The amended proviso will read as follows :—

"Provided that this Rule shall not apply to such a member appearing as "amicus curiae" or without a fee on behalf of a Bar Council, Incorporated Law Society or a Bar Association".

II. Amendment of Rule 6, Part VI, Chapter II.

At the last meeting the Council also amended Rule 6, Part VI, Chapter II as set out in the following Resolution :—

RESOLUTION NO. 11/1991

"RESOLVED that the following proviso be added to Rule 6 of Rules in Part VI Chapter II :—

"For the purposes of this rule, Court shall mean a Court, Bench or Tribunal in which above-mentioned relation of the Advocate is a Judge, Member or the Presiding Officer."

SHYAM MOHAN SRIVASTAVA
Secretary

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110001, the 9th August 1991

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1350.—WHEREAS M/s. Kamala Solvents (P) Ltd., Karur Road Dindigul-4 (TN/20053) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Madurai from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1-5-89 to 30-4-92.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along-with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt./1356.—WHEREAS M/s. Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd., B.H.P.V. Post Office, Vjsakhapatnam-12 (AP/3495) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. S-35014(262)/82-PF II (SS II) dated 7-4-1986 and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years with effect from 18-12-88 to 17-12-91 upto and inclusive of the 17-12-91.

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintained such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, along with translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if ——— on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the Payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims completes in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1991